लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 नवंबर 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक -29

"शुभम् करोति कल्याणम्
आरोग्यम् धन संपदा। शत्रु वृद्धि
विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।

आत्मनिर्भरः औद्योगिकरण के जरिए बढ़ता रोज़गार 3

आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल अवशेषों का निदान 6

नानक तेरा - तेरा 8

7 साल बेमिसाल

डा. चंद्र त्रिखा

27 अक्तूबर 2019 को प्रदेश में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हुई थी। राजनीतिक साझेदारी के दो साल पूरे करते हुए मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के सात साल पूरे कर लिए हैं। सरकार इस वर्षगांठ को आमजन के बीच पहुंच कर मना रही है। राज्य सरकार के सात साल के इस कार्यकाल पर नजर दौड़ाई जाए तो करीब डेढ़ सौ ऐसे काम दिखाई देते हैं जो इस सरकार को दूसरी सरकारों से अलग करते हैं, लेकिन नेतृत्व सात प्रमुख उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहा है।

इस अवधि में जनहित की 551 सेवाओं को 'ऑनलाइन' किया गया जिससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ। नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल बनाया और बार-बार की फीस बंद की गई। कर्मचारियों, खासतौर से शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। 'सीएम विंडो' पर सात लाख शिकायतों का निवारण किया। कुल 20 विभागों और 22 जिला उपायुक्तों के कार्यालयों में ई-आफिस की सुविधा दी गई।

'परिवार पहचान पत्रों' के जरिए वास्तविक गरीबों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बीपीएल परिवार की आय सीमा एक लाख 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपए की गई। गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह शगुन 50 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपए किया गया। गरीब रेहड़ी वालों को बिना गारंटी 10 हज़ार का लोन और मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की मदद शुरू की गई। गरीब परिवारों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी गरीबों का 383 करोड़ का मुफ्त इलाज किया। सरकारी नौकरियों में पर्ची व खर्ची बंद की गई और योग्यता पर आधारित नौकरियां दी गई। एकल पंजीकरण सुविधा के बाद साढे चार लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया। प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां व गांवों में विकास की सुविधा दी गई। स्कूल व कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की विशेष तैयारी की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में 'इंटरव्यू' सिस्टम खत्म किया गया। राज्य के 18 लाख बुजुर्गों को 2,500 रुपए माहवार पेंशन शुरू की गई और 60 लाख से अधिक आयु के श्रमिकों को 2,750 रुपए की सहायता दी गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रीमियम का सरकारी खाते से भुगतान किया गया। बुजुर्गों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई।

किसानों के लिए जोखिम-मुक्त खेती, फसल खरीद पर ऑनलाइन भुगतान, बेहतर जल प्रबंधन, सुशासन एवं पारदर्शी सरकार, सामाजिक सुरक्षा, मैरिट पर नौकरियां तथा गरीब कल्याण की ऐसी सात योजनाएं हैं जिन्हें सरकार की विशेष उपलब्धि कहा जा सकता है।

पिछली कांग्रेस सरकार के समय का बकाया मुआवज़ा किसानों को इस सरकार ने दिया। फसल का खराब होने पर मुआवज़ा राशि छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रति एकड़ की गई। फसलों के खराबे का आकलन 50 की बजाय 33 प्रतिशत खराबे पर शुरू हुआ। 'फसल बीमा योजना' लागू की और चार हजार करोड़ रुपए की राशि दी। फसल बीमा से वंचित किसानों को 12 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया।

'पशुधन क्रेडिट कार्ड' योजना में 733 करोड़ के ऋण दिए गए। वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र दोगुना व उत्पादन तीन गुना बढ़ाने के लिए काम शुरू किया। प्रदेश में 11 फसलों की खरीद एमएसपी दर और भुगतान 72 घंटे में सीधे खातों में करने की व्यवस्था की गई। गन्ने का सबसे अधिक भाव 362 रुपए क्विंटल तय किया गया।

बाजरा 'भावांतर भरपाई योजना' में शामिल किया गया और 600 रुपए क्विंटल की सब्सिडी तय की गई। कुल 21 फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया। किसान को 72 घंटे में भुगतान नहीं होने पर नौ फीसदी ब्याज देने की व्यवस्था की गई। सभी योजनाओं का ऑनलाइन भुगतान किया गया। हर खेत को पानी देते हुए नांगलचौधरी में टेल तक पानी पहुंचाया। पुराने नहरी जलतंत्र को दुरुस्त किया गया। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने पर जोर। सोलर पंप लगाने पर किसानों को सब्सिडी देने की योजना लागू की गई।। ये विकास यात्रा जारी है।

मनोहरलाल हरियाणा के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री - मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें हरियाणा में लंबे वक्त तक काम करने का अवसर मिला है और अनेक सरकारों को नजदीक से काम करते देखा है लेकिन हरियाणा को पांच दशकों में मनोहर लाल के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदार सरकार मिली है। प्रधानमंत्री मोदी झज्जर जिला के बाढ़सा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये गए विश्राम सदन के शुभारम्भ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदार कार्यशैली पर मुहर लगाते हुए कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार हर समय प्रदेश की भलाई के लिए सोचती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास का मूल्यांकन किया जाए तो पिछले पांच दशकों की सबसे उत्तम और सबसे रचनात्मक तरीके से काम करने वाली मनोहर सरकार हरियाणा को मिली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा 'मैं मनोहर लाल जी को लंबे समय से जानता हूं, सीएम बनने के बाद तो उनकी प्रतिभा और निखार आया है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार उनके नेतृत्व में इनोवेटिव काम कर रही है कई बार उस कार्य शैली को केंद्र सरकार भी अपनाती रही है। यही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रेरणा स्त्रोत बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री एवं उनकी टीम को बधाई देता हूं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वह हरियाणा के सुखद भविष्य की नींव में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने गौरवान्वित होते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश आज मनोहर लाल के नेतृत्व में देश के उज्ज्वल भविष्य की ताकत बन रहा है।

भेदभाव की नीति, अब नहीं चलती

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही संकल्प लिया था कि सरकारी तंत्र से भाई-भतीजावाद समाप्त किया जाएगा, इससे समाज में भेदभाव का रोग फैलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' का नारा दिया और सबको विश्वास में लेते हुए विकास की राह पर निकल पड़े। श्री मनोहरलाल ने जता दिया था कि प्रदेश के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े।

कठोर परिश्रम व ईमानदारी से आगे बढ़ते उन्होंने न केवल अपने सहयोगी जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा दी बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले को भी इसके लिए तैयार कर लिया। हर एक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया गया जिसका परिणाम आज सबके सामने हैं। लोगों का जीवन सहज व सरल हुआ है। सरकारी नौकरियों में काबिलियत के आधार पर नौकरी व विभागों में ऑनलाइन तबादलों ने सियासत की तस्वीर ही बदल डाली।

पिछली सरकार के दौरान नौकरियों में भाई-भतीजावाद, जातपात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं का बोलबाला था। लिखित परीक्षाएं मात्र औपचारिकता थीं। चहेतों को लाभ पहुंचाया जाता था। जनप्रतिनिधियों के लिए कोटे निर्धारित होते थे, जिसके चलते युवाओं में यह भावना घर कर गई थी कि बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी संभव नहीं है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के युवाओं की इस पीड़ा को समझा है और योग्यता के आधार पर और पारदर्शी ढंग से नौकरियां देने की व्यवस्था कर डाली।

ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। पुलिस भर्ती में भी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की गई है। युवाओं का योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का सपना साकार हो रहा है। नौकरी के लिए आज किसी को न तो जेवर बेचने की जरुरत है और न जमीन। पढ़ो और आगे बढ़ो।

आज युवा किसी जुगाड़बाजी की तलाश नहीं करते, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की चर्चा करते हैं। इसका सुखद परिणाम यह रहा है कि प्रदेश के युवा राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कभी आईएएस के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में हरियाणा के इक्का-दुक्का उम्मीदवार ही सफलता पाते थे। लेकिन अब यह संख्या 50 को पार कर गई है।

यूपीएससी व एचसीएस के जरिए बनने वाले अधिकारियों के बारे में आम आदमी को पता ही नहीं चलता था, कि ये बनते कैसे हैं। आज एक आम परिवार को अचानक ख़बर मिलती है कि उनका बेटो या बेटी का आईएएस या एचसीएस के लिए चयन हुआ है। इस साल सिविल सेवा में हरियाणा से कुल 56 प्रतिभाओं का चयन हुआ है। इनमें से 21 लड़कियां व 35 लड़के हैं।

- मनोज प्रभाकर

संपादकीय

हरियाणा एक : हरियाणवी एक

हरियाणा अपनी स्थापना के 55 वर्ष पूरे कर चुका है। अब 56वें वर्ष में प्रवेश से एक सप्ताह पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने पूरी सहृदयता के साथ प्रवेश की विकास गति को पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि हमारे प्रदेश हरियाणा द्वारा क्रियान्वित की गई अनेक ऐसी योजनाएं जो कभी-कभी पूरे राष्ट्र को प्रेरित करती हैं।

वस्तुतः प्रधानमंत्री ने अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करते हुए प्रत्येक हरियाणा वासी की कर्मठता एवं पारस्परिक सद्भाव की सराहना की है।

'हरियाणा एक हरियाणवी अनेक' सरीखे लक्ष्यों को लेकर जिस मनोयोग से हरियाणा की वर्तमान सरकार और पूरा सरकारी तंत्र कार्यरत है, वह इस बात का द्योतक है कि यदि संकल्प दृढ़ हों और दिशा स्पष्ट हो तो किसी भी सीमा तक विकास को तीव्र गति दी जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की सरकार ने अपनी दूरदर्शिता से अपने इस प्रदेश को जातिवाद व क्षेत्रवाद की अंधी गुफ़ा से बाहर निकाला है।

हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज का संकल्प पूरे देश में एक नया कीर्तिमान है। मैडिकल कॉलेज होगा तो उसके साथ-साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित अस्पताल होंगे। हम किसी भी स्वास्थ्यगत आपदा से जूझने के लिए सदा तत्पर रहेंगे।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास, हर जिले में मैडिकल कॉलेज तथा हर जिले में विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य। इस प्रदेश के लिए एक नव-संकल्प है।

इसके अतिरिक्त क्लस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय, 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज का भी संकल्प लिया गया है।

हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम लोगों के 'क्लस्टर' स्थापित किए जा रहे।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया विकास मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' हमारा मार्गदर्शक भी हैं और नई नीतियों का केंद्र बिन्दु भी।

अब जबकि वर्तमान सांझा सरकार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, ये सभी उपलब्धियां वैशिष्ट्य से भरी हैं।

- डा चंद्र त्रिखा

स्वस्थ हरियाणा

अस्पताल में जाने से पहले एडवांस रजिस्ट्रेशन

राजकीय अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी कार्ड बनवाने तथा उपचार के लिए लंबी लाइन में इंतजार न करना पड़े इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 'स्वस्थ्य हरियाणा' नाम से एक ऐप तैयार की है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी मरीज प्रदेश के किसी भी नागरिक अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गत दिनों यह ऐप लॉंच की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड के प्रकोप को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस अभियान को और सार्थक बनाने के लिए स्टेट हैल्थ सिस्टमस रिसोर्स सेंटर (एचएसएचआरसी) ने 'स्वस्थ हरियाणा' मोबाइल ऐप बनाई है।

उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से अस्पताल में जाने से पहले मरीज घर बैठे अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे तथा प्रदेश के अस्पतालों में लोगों की भीड़ का सुव्यस्थित तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा। मरीज को किस डॉक्टर व किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है । मरीज को लाइनों में नही लगना पड़ेगा व समय की बचत भी होगी तथा सीधे जाकर डॉक्टर के पास इलाज करवा सकता है।

डॉक्टर जो टेस्ट लिखेगे और जो भी लैब की रिपोर्ट होगी इस ऐप के माध्यम मरीज अपनी लैब रिपोर्ट घर बैठे ऐप से फोन पर देख पाएंगे। ऐप में रोगी की हिस्ट्री स्टोर रहेगी, वह कभी भी देख सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मोबाइल ऐप में और भी कई सुविधाएं हैं जिनमें ब्लड बैंक की जानकारी (ब्लड बैंक ई-रक्तकोष से लिंक है तथा ब्लड युनिटस की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकती है), जच्चा-बच्चा देखभाल व टीकाकरण सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों तथा तीन मेडिकल कॉलेजों में आम जन घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे व अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

जांच रिपोर्ट का रिकार्ड तिथि अनुसार उपलब्ध होगा और मरीजों को इस ऐप द्वारा निकटतम ब्लड बैंक की भी जानकारी उपलब्ध होंगी।

माधोगढ़ का किला और रानी तालाब

ढोसी पर्वत को जहां तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, वहीं माधोगढ़ किला पर अधिक से अधिक पर्यटन लाने के लिए आने वाले समय में माधोगढ़ के राजा महल का भी निर्माण किया जाएगा। दोनों पर्वत स्थल पर्यटन के रूप में विकसित होंगे तो इस इलाके में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास किए जाते हैं। ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी इतिहास की जानकारी हासिल कर सकें। इसी श्रृंखला में महेंद्रगढ़ जिले के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। माधोगढ़ किला पर रानी तालाब के पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है तथा रानी महल का कार्य भी अंतिम चरण में है। इस काम पर नौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढोसी पर्वत व माधोगढ़ किला का भ्रमण किया। महेंद्रगढ़ जिला में एक साथ कई हाईवे का निर्माण हो रहा है। ऐसे में यहां पर्यटन गतिविधियों के साथ रोज़गार के नए अवसर भी खुलेंगे।

ढोसी पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थयात्री यहां आसानी से पहुंच सके इसके लिए सड़क मार्ग बनाया जाएगा। सड़क बनने के बाद यहां पर अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। ढोसी पर्वत को बेहतरीन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे पहले थाना गांव की तरफ से सड़क मार्ग बनाया जाएगा। पर्वत पर चढ़ने से थोड़ा पहले ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि पर्वत पर किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। इसके बाद कुलताजपुर गांव की तरफ से पीपीपी मॉडल पर रोप-वे बनाया जाएगा।

यहां पर चवन ऋषि जैसे महान तपस्वी हुए हैं। ऐसे में सड़क मार्ग बनने के बाद इस जगह पर आयुष विभाग की ओर से पंचकर्म तथा आयुष वैलनेस का बड़ा केंद्र भी खोला जाएगा। इस सेंटर में पर्यटक स्वास्थ्य लाभ लेंगे। एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहां पर पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।

महेंद्रगढ़ जिला को 1358.68 लाख रुपए की सौगात

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माधोगढ़ किला से जिला को 1358.68 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आजम नगर सीहोर के 33 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह सब स्टेशन 299.85 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। सतनाली में बनने वाली सीएचसी का भी शिलान्यास किया गया। इस भवन पर लगभग 1,058.83 लाख रुपए खर्च होंगे।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

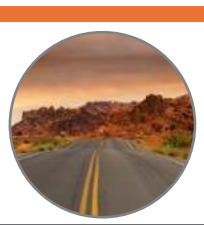

पंचकूला महानगरीय विकास को पंचकूला-मोरनी सड़क प्रोजेक्ट और गति प्रदान करेगा। इससे मोरनी क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा, विधवा व विकलांग सम्मान भत्ते में 250 रुपए वृद्धि करते हुए 2750 रुपए प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल के मुताबिक यह राशि एक नवंबर से लाभार्थियों को देनी शुरू कर दी जाएगी।

आत्मनिर्भरः औद्योगिकरण के जरिए बढ़ता रोज़गार

उद्योगों से रोज़गार को बढ़ावा

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक पॉलिसी 'हरियाणा औद्योगिक एवं रोज़गार नीति-2020', 'रोज़गार सृजन सब्सिडी योजना' आदि ऐसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिनके कारण एटीएल, फ्लिपकार्ट, मारुति, अमेजन इंडिया, वॉलमार्ट वृद्धि, हकदर्शक जैसी बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश के लिए निरंतर आ रही हैं। इससे जहां हरियाणा की आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा प्रदेश में बड़ी कंपनियों के आने से छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र सरकार द्वारा एचएसआईआईडीसी 'परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी' के रूप में चुना जाना तथा सोहना में इलेक्ट्रॉनिक-मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) स्थापित होना प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

-दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा में निवेश एवं रोज़गार बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निरंतर रंग ला रहे हैं। जानी-मानी ई-कॉमर्स कंपनियां भी हरियाणा में अपने पैर पसार रही है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों में तेज़ गति से आर्थिक विकास देखा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी जीएसडीपी विकास दर के आंकड़ों के अनुसार 2020 में हरियाणा को शीर्ष तीन सबसे तेज़ी से बढ़ते राज्यों में स्थान दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने ज़मीनी स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। एमएसएमई की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राज्य में एमएसएमई निदेशालय और प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिला एमएसएमई केंद्र (डीएमसी) स्थापित किए है।

मज़बूत नीति ढांचा

एमएसएमई का समर्थन करने के लिए, उन्हें व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करने के लिए, राज्य ने पथ-प्रदर्शक हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी) 2020 शुरू की है। इस नीति में रोज़गार सृजन, उद्यमिता विकास, निर्यात प्रोत्साहन, ग्रामीण उद्यमिता और राज्य भर में आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मज़बूत करने और हरियाणा ब्रांड को मज़बूत करने पर प्रमुख स्थान दिया गया है। एचईईपी 2020, हरियाणा की एमएसएमई नीति-2019 के संयोजन में यह सुनिश्चित करेगी कि एमएसएमई को सभी एमएसएमई विकासात्मक कार्यात्मक क्षेत्रों में राज्य सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

राज्य के एमएसएमई को तकनीकी रूप से उन्नत करने के लिए, राज्य सरकार ने कलस्टर विकास दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह राज्य सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के निर्माण के लिए भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना का एक सक्रिय अधिवक्ता और प्रचारक है। हरियाणा सरकार 67 करोड़ रुपए से अधिक के भारत सरकार के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ योजना के तहत छह परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है।

कलस्टर विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य ने हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति 2020 के हिस्से के रूप में प्रमुख मिनी कलस्टर विकास योजना के तहत समर्थन को 1.80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.50 करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि योजना के तहत हस्तक्षेप पहले ही 40+ से अधिक कलस्टरों में शुरू हो चुका है, 16 समूहों में हस्तक्षेप निदेशालय की स्थापना के बाद से पिछले वर्ष में ही शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सीएफसी बनाने के लिए कुल 31 करोड़ रुपए का राज्य सरकार का समर्थन जारी किया गया है, जिसमें से 11 करोड़ रुपए निदेशालय की स्थापना के बाद जारी किए गए है।

नया उद्यम विकास

राज्य सरकार नए उद्यम निर्माण पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ अपनी तरह के एक ब्लॉक स्तरीय उद्यम

विकास कार्यक्रम की संकल्पना कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सतत रोज़गार और उद्यमिता के अवसरों पर ज़ोर देने के लिए ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना है। स्थानीय रूप से प्रासंगिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा और राज्य के किसानों को उत्पादकों से लेकर प्रोसेसर तक अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में 140 ब्लॉकों में केंद्रित उत्पादों की पहचान करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है, और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजना चल रही है।

उन्नत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण

हरियाणा में एक समग्र खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, राज्य अपनी महत्वाकांक्षी हरियाणा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 को लागू कर रहा है। नीति का उद्देश्य कृषि स्तर पर मज़बूत बुनियादी ढांचे का विकास करना और अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य में तकनीकी रूप से उन्नत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करना है। नीति के तहत, अब तक 195 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 28 करोड़ रुपए के सरकारी अनुदान घटक और 165 करोड़ रुपए से अधिक की निजी भागीदारी शामिल है। इन परियोजनाओं से राज्य के 8,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा और 2,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होगा।

ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कायम (पीएमईजीपी) देश में ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। राज्य सरकार की नोडल एजेंसी होने के नाते एमएसएमई निदेशालय राज्य में कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। इस योजना के तहत, ग्रामीण हरियाणा में 16,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोज़गार पैदा करने वाली मार्जिन मनी के रूप में 65 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया गया है।

वितरण किया गया है।

एचईईपी 2020 के हिस्से के रूप में, राज्य सरकार ने ग्रामीण उद्यमिता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना भी शुरू की है। यह योजना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला प्रदान करती है जैसे कि पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी आदि।

बाज़ारों तक पहुंच

एमएसएमई के लिए डिजिटल क्षमता, सशक्तिकरण और बढ़ी हुई बाज़ार पहुंच पर केंद्रित बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स खिलाड़ियों - ईबे, पावर2एसएमई और ट्रेड इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगों के माध्यम से, राज्य सरकार का इरादा पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर 3,000 से अधिक एमएसएमई को हैंड होल्डिंग और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना है।

एमएसएमई को नए बाज़ारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ सहयोग किया है।

-संगीता शर्मा

पिछले सात वर्षों में फरीदाबाद में सड़कों व पुलों के विकास में बेहतरीन कार्य हुए हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू हो चुका है। फरीदाबाद से केजीपी व ताज एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए एक नया हाईवे मंजूर किया गया।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 'प्रथम ई-व्हीकल' खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। प्रदेश में राज्य/राष्ट्रीय या अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ई-मोबिलिटी में शोध एवं विकास के लिए पांच करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

बदली सोच सतत विकास

मैं हरियाणा हूं। मैं वर्ष 1966 में अपने अस्तित्व में आया। गीता का संदेश मेरी मूल संस्कृति है। विगत 55 साल की यात्रा में मैंने प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए अनेक राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान मेरे सामने चुनौतियां कम नहीं रही। वैश्विक बदलाव के चलते बड़ी चुनौती भी थी, ऐसे में चुनौती यह भी थी कि अपनी संस्कृति को कैसे बनाकर रखा जाए। 'दूध दही का खाणा - ईसा म्हारा हरियाणा।' मेरी संस्कृति का एक खास पहलू है, जिसके बलबूते आज मेरे अनेक जवान सीमाओं के प्रहरी हैं और अनेक बेटे-बेटियां खेल के मैदान में डंका बजा रहे हैं।

कालांतर में मेरी पहचान एक ऐसे प्रदेश के रूप में बनी जिसमें छोरों के मुक़ाबले छोरियों की संख्या कम हो गई थी। तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। इस दाग़ को धोने के लिए भी मैंने हुंकार भरी और आज 1,000 छोरों के मुक़ाबले छोरियों की संख्या 900 से पार पहुंच गई है। बात करूं खेत खलिहानों की तो मेरी मिट्टी में किसानों ने पसीना बोकर सोना उपजाया है। मैं एक मात्र ऐसा प्रदेश हूं जिसे देश में धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर खेती अब घाटे की बजाय केवल मुनाफे की होती है। मिट्टी से लेकर मार्केट तक राज्य सरकार किसान के साथ है। फसल के वाजिब और पूरे दाम मिलते हैं। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई 'फसल बीमा योजना' व 'भावांतर भरपाई योजना' से होती है।

1955 में उठी हरियाणा की मांग

संयुक्त पंजाब से हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के शासनकाल में प्रमुखता से उठी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा था। 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के शासनकाल में पंजाब प्रांत की भाषा को लेकर विरोध उत्पन्न हो गया। हिंदी भाषा क्षेत्रों में पंजाबी बढ़ाने का विरोध हुआ, परिणाम स्वरूप इसके समाधान के लिए सच्चर फार्मूला बनाया गया। पहली अक्तूबर 1949 को सच्चर फार्मूले को लागू कर दिया गया, इस फार्मूले के अनुसार पंजाब को पंजाबी क्षेत्र व हिंदी क्षेत्र में बांट दिया गया।

1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारित करने रोहतक आए आयोग के समक्ष हरियाणा के विधायकों ने पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी। पंजाब के प्रताप सिंह कैरों के शासनकाल (1956-64) के दौरान ही पृथक हरियाणा की मांग ने ज़ोर पकड़ा। भारतीय संविधान में संशोधन (17 वा संशोधन 1956) होने के बाद राष्ट्रपति की आज्ञा से 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला राज्य में लागू कर दिया। प्रताप सिंह कैरों ने इसे पूरी तरह सफल होने के अवसर नहीं दिये। इससे क्षेत्रीय योजना असफल हो गई।

23 सितंबर 1965 को लोगों के दबाव में सरकार ने विभाजन के लिए सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के फैसले को सही मानते हुए देश के गृहराज्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर्गठन के संबंध में संसदीय समिति के गठन संबंधी निर्णय की घोषणा कर दी। हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जे सी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया। 18 सितम्बर, 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया तथा एक नवंबर 1966 को पृथक राज्य के रूप में हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

बदल गई दिशा और दशा

मनोहर सरकार ने जब से प्रदेश की शासनिक प्रशासनिक बागडोर संभाली तब से सूबे की दिशा और दशा बदलती चली आ गई। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रारंभ में ही संकल्प लिया था कि प्रदेश के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हर वह संभव प्रयास करेंगे, इसके लिए चाहे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। ईमानदारी, साफ नीयत व कठोर परिश्रम से उन्होंने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र लिया और आगे बढ़ते चले गए। सरकारी नौकरियों में काबिलियत के आधार पर नौकरी व विभागों में ऑनलाइन तबादलों ने तो पूरी व्यवस्था की बदल डाली है।

पंचायती राज संस्थाएं

प्रदेश में अंतर जिला परिषद् का गठन किया है। इस परिषद् का गठन करके ग्रास रूट के जन प्रतिनिधियों के लिए प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए मिल बैठकर व आपसी विचार-विमर्श से विकास की प्राथमिकताएं तय करने के लिए एक संस्थागत मंच उपलब्ध हुआ।

पंचायतें गांवों की सरकार मानी जाती हैं। इसलिए प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अधिकार दिये गए। उन्हें स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं में और सुधार के लिए मतदाताओं को 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार भी दिया गया है। सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में, शहरी निकायों को मज़बूत करने के लिए मेयर का चुनाव सीधे ही करवाया है।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मज़बूत करने के लिए सम्पत्ति के पंजीकरण पर लगाये गये स्टाम्प शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व इन्हें प्रदान किया जाता है।

ग्रामीण विकास

एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले पांच करम के सभी कच्चे रास्तों को पक्का किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 तक 1225 कि.मी लम्बे 475 कच्चे रास्ते 490 करोड़ रुपए की राशि से पक्के किये जाएंगे।

ग्राम दर्शन पोर्टल पर राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें विकास परियोजनाओं व पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों का विवरण शामिल है। ई-कनेक्टिविटी सुविधा से युक्त 1,874 ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं। 6,188 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, 5,733 ग्राम पंचायतों में 8,468 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं।

ऑनलाइन सेवाएं और समाधान

आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए 'सीएम विंडो पोर्टल' शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 8 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सरकार की अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। प्रदेश में लगभग 20 हजार अटल सेवा केंद्रों और 117 अंत्योदय एवं सरल केंद्रों के माध्यम से 42 विभागों की 573 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

जनता के प्रति प्रशासन की जबाबदेही तय करने और समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' शुरू किया गया है। इससे 546 सेवाओं को जोड़ा गया है। इन सेवाओं के आवेदकों को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है, तो उसकी अपील स्वतः ही उच्चाधिकारी के पास हो जाती है। वहां भी समय पर सेवा न मिले, तो राइट टू सर्विस कमीशन को भी अपील स्वतः ही चली जाती है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई है।

एकल पंजीकरण

युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए 'एकल पंजीकरण' की सुविधा शुरू की गई है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए 'कॉमन पात्रता परीक्षा' का प्रावधान भी किया गया है।

भ्रष्टाचार पर लगाम

प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन पर सी.एल.यू देने में होता था। सी.एल.यू. की पूरी प्रक्रिया को ही अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सभी सी.एल.यू. 30 दिन में हो जाते हैं और सी.एल.यू. परमिशन भी ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है।

भू-रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली लागू की गई है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है।

जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों आदि के बेबाकी प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किये जाते हैं।

हैल्पलाइन सेवा

संकट के समय लोगों की मदद के लिए 'हरियाणा हैल्पलाइन सेवा-112' शुरू की गई है। प्रदेश-भर में 600 से अधिक गाड़ियां इस सेवा के लिए लगाई गई हैं। अब किसी भी अपराध, आगजनी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि के समय इस एक ही नंबर पर बटन दबाकर मदद ली जा सकती है। अब 100, 101 और 108 नंबरों पर दी जाने वाली सेवाएं भी इस नंबर के साथ जोड़ दी गई हैं। इस नंबर पर 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी और कॉल करते ही 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंच जाएगी।

पर्यटन को प्रोत्साहन

पंचकूला को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के अलावा हथिनीकुंड और अरावली की पहाड़ियों में स्थित महर्षि च्यवन की तपोभूमि ढोसी में भी पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जिला पंचकूला के टिक्कर ताल और मोरनी में पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर जैसी एयरो स्पोर्ट्स व वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की गई हैं। महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ का किला और रानी तालाब को संवारे जाने की योजना है।

इस पैकेज में पर्यटकों को जिले के

हरियाणा सरकार ने एक्सग्रेसिया के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मृतक सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि एक लाख रुपए देने के लिए संबंधित विभाग के मुखिया को अधिकृत कर दिया है।

हरियाणा सरकार द्वारा सैनिकों के 20 प्रतिशत निशक्तता के मामलों में अनुग्रह राशि बढ़ाकर 15 लाख, 50 प्रतिशत निशक्तता में 25 लाख और 100 प्रतिशत निशक्तता में अनुग्रह राशि बढ़ाकर 35 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।

बदला हरियाणा.. से सशक्त हरियाणा

पारदर्शिता, विकास व हर्ष
5+2
जन सेवा के सात वर्ष

आध्यात्मिक स्थलों का भी भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। इन स्थलों में टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स, यादवेंद्र उद्यान (पिंजौर), मांधना जैसे पर्यटक स्थलों के साथ-साथ श्री माता मनसा देवी मंदिर, कालका जी मंदिर और गुरुद्वारा नाडा साहिब के अलावा और भी कई धार्मिक स्थल शामिल हैं।

हथिनीकुंड बैराज और रोहतक स्थित तिलियार झील में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर गतिविधियां शुरू करने के लिए कार्य-योजना तैयार की गई है।

पर्यावरण संरक्षण

हरियाणा सरकार ने पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया है। 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 2,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी की जाएगी।

प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना की शुरुआत की गई है। इन ऑक्सीवनों में आम आदमियों के भ्रमण के लिए ट्रैक, साइकिल ट्रैक आदि की व्यवस्था होगी। पंचकूला और करनाल में ऑक्सीवनों की स्थापना का कार्य चल रहा है। पंचायतों की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10 प्रतिशत भूमि पर ऑक्सीवन स्थापित किये जाएंगे।

पेड़ों की खेती को ऑक्सीजन की खेती मानते हुए 'ऑक्सीजन खेती पर प्रोत्साहन राशि योजना' शुरू की गई है। इसमें किसान को तीन साल तक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके बाद किसान ऑक्सीजन की खेती से आय प्राप्त कर सकेगा। ऑक्सीवन की खेती करने वाले किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधरोपण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत की गई है।

आयुष्मान भारत योजना

प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ता। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवारों का प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाया जाता है।

प्रदेश में 231 प्रकार के ऑप्रेशन, 69 प्रकार के टेस्ट और 23 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती हैं। साथ ही 766 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों के महत्व को भी समझते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए 'आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर' स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

खेल नीति से निखरता 'सोना'

प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वर्ष 2020 में सम्पन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत के सात पदकों में से तीन हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में भी भारत के 19 पदकों में से छह पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।

राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। राज्य में 2 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 22 जिला स्तरीय खेल परिसर, 12 उपमंडल स्तरीय और 160 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर स्थापित हैं।

पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतू ''हरियाणा राज्य डेवेल्पमेंट फंड'' का गठन किया है। हमने अब तक 14 हजार से अधिक खिलाड़ियों को 400 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा 28 हजार 643 खिलाड़ियों को 50 करोड़ 38 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को छह करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को चार करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को अढाई करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय

भौतिक रूप से किसी देश व प्रदेश की खुशहाली को नापने के लिए वहां के लोगों की आय को ध्यान में रखा जाता है। इस दृष्टि से हरियाणा देश के गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2 लाख 39 हजार 535 रुपए है, जो देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1 लाख 28 हजार 829 रुपए से काफ़ी अधिक है।

टीकाकरण

प्रदेशवासियों को कोविड-19 से सुरक्षा कवच प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। अब तक प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 2 करोड़ 54 लाख 26 हजार 352 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 76 लाख 31 हजार 795 को पहली डोज तथा 77 लाख 94 हजार 553 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।

सितंबर, 2021 में हुए कोविड-19 के सीरो सर्वेक्षण के तीसरे राउंड की रिपोर्ट में राज्य के लोगों में सीरो पॉजिटीविटी रेट 76.3 प्रतिशत (शहरी 78.1 प्रतिशत और ग्रामीण 75.1 प्रतिशत) पाया गया। पहले सीरो राउंड में पॉजिटीविटी रेट आठ प्रतिशत तथा दूसरे सीरो राउंड में 14.8 प्रतिशत पाया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य है। हरियाणा में यह अनुपात 32 प्रतिशत है और इसे 2030 से पहले ही 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, प्रदेश में 4,000 प्ले-वे स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि नई शिक्षा नीति में तीन साल की आयु से बच्चे की शिक्षा आरंभ की जा सके। अब तक 1135 प्लेवे स्कूल खोले जा चुके हैं।

प्राइवेट स्कूलों की तर्ज़ पर सुविधाएं और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए 113 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 136 हो गई है।

परिवार पहचान-पत्र

गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' चलाई गई है। इसके तहत पहले एक लाख सबसे गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 1 लाख रुपए से कम आय वाले 50 हजार परिवारों की पहचान कर ली गई है।

इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन करके परिवारों की पहचान की जाती है। इसके प्रथम चरण में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य है।

इन परिवारों की इस वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए आय सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्ष 2025 तक सभी परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है।

फसल विविधिकरण

फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए ''मेरा पानी-मेरी विरासत'' योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें कृषि वानिकी को भी जोड़ा गया। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को तीन वर्ष तक 10 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन दिया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। फसलों का भुगतान 72 घंटे के भीतर सीधा किसानों के खातों में किया जाता है। गन्ना उत्पादकों को देशभर में 362 रुपए प्रति क्विंटल का सर्वाधिक भाव दिया जा रहा है। हरियाणा की सभी टेलों पर पानी पहुंचाया गया है।

- मनोज प्रभाकर

हरियाणा सरकार ने राज्य के पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 हेतु डाईट-भत्ता व खेल-किट की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा परिवहन विभाग के बेड़े में 809 बसों की खरीद की गई हैं। मार्च माह तक और भी बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी।

प्रदेशभर में डीएपी की कोई कमी नहीं

कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं। रबी सीजन के लिए तीन लाख मी.टन यानि 60 लाख बैग डीएपी एलोकेट हो चुकी है। यह पिछले पांच सालों की एवरेज से 20 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे ज़रूरत के अनुसार ही डीएपी व अन्य रसायनिक खाद खरीदें। किसान आगामी फसलों के लिए अभी से खाद का स्टॉक न करें। नवंबर और दिसंबर माह के दौरान में फसल बिजाई में किसानों के समक्ष डीएपी व यूरिया की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सर्वाधिक फसलें खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने किसान हितैषी योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए विविधिकरण पर ज़ोर दिया गया है। प्रदेश के एक लाख गरीब परिवारों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर चिह्नित करके आमदनी बढ़ाई जाएगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।

किसानों के हित में योजनाएं

दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए हितकारी साबित हुई है। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है और इससे अन्य प्रदेशों से बाजरा हमारी मंडियों में नहीं आएगा। बाजरा उत्पादन किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 11 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं जबकि पड़ोसी प्रांत राजस्थान व पंजाब में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए हर हित स्टोर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रिक-ट्रैक्टर

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रिक-ट्रैक्टर विकसित किए जाने पर पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक-ट्रैक्टर आने से किसानों की आय में वृद्धि होगी ।

उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक ट्रैक्टर की इस इलेक्ट्रिक-तकनीक को ब्रान्ड के रूप में विश्व बाजार तक लेकर जाएं, इससे ''लोकल से ग्लोबल'' तक ले जाने का सपना साकार होगा। इसके साथ ही आमजन का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रूझान बढ़ेगा। देश और दुनिया में स्वच्छ पर्यावरण व प्रदूषण कम करने में इलेक्ट्रोनिक वाहन उपयोगी सिद्ध होंगे।

दत्तात्रेय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम योजना शुरू की है। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना पर चालू वित्त वर्ष के दौरान 10,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।। सरकार द्वारा इस योजना के दूसरे चरण को 2024 तक बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को आह्वान किया कि वे अपने संस्थानों में इस प्रकार के वाहनों की अनुसंधान तकनीक विकसित करके मार्केट में उतारें और विश्व बाजार में भाग लेने के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कदम होगा।

संवाद ब्यूरो

आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल अवशेषों का निदान

आधुनिक कृषि यंत्रों ने कृषि को आसान बना दिया है। कृषि यंत्रों की मदद से जहां फसल अवशेषों को काटकर छोटा किया जा सकता है, वहीं वातावरण को प्रदूषण मुक्त कर खेत की जुताई आसानी से की जा सकती है। राज्य सरकार फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को जागरूक कर रही है। रैपर, सुपर सिडर, रोटावेटर, बेलर मशीन, सुपर एसएमएस जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिये अवशेषों को छोटा किया जा सकता है। ये यंत्र अवशेषों को मिट्टी में मिलाने व छोटा करने का कार्य करते हैं। इन कृषि आधुनिक यंत्रों पर सरकार 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है।

मोबाई वैन से जागरूकता

राज्य सरकार ने प्रदेश के 13 ऐसे जिले चयनित किये हुए हैं जिनमें ज्यादातर किसान धान व बाजरे की खेती करते हैं। इन जिलों में सरकार इस बात को लेकर गंभीर है की धान की कटाई के बाद किसान कहीं फसलों के अवशेषों ना जला दें। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत,पानीपत, रोहतक,जींद,कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, युमनानगर व अंबाला में किसानों को जागरूक करने को लेकर माबाईल वैन गांव-गांव जाकर धान, बाजरा व अन्य फसलों के अवशेषों को ना जलाने का संदेश जहां दे रही हैं वहीं गेंहू की सीधी बिजाई करने का संदेश भी दे रही हैं। सरकार का जोर फसल अवशेष ना जलाने पर है। इसके लिए बड़े स्तर पर किसान गोष्ठियां व कृषि सेमीनारों का आयोजन किया जा रहा है।

कैसे करें आवेदन

इन कृषि उपकरणों को प्राप्त करने के लिए किसान साईट पर जाकर आन लाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर आरसी नंबर, पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण जरूरी है।

क्या कहते अधिकारी

पानीपत के सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार का कहना है की किसान समूह पंजीकरण करवा कर 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत स्तर 50 प्रतिशत सब्सीडी पाकर तक इन कृषि उपकरणों का लाभ ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जो किसान आवेदन करते हैं। उपायुक्त द्वारा गठीत कमेटी उन किसानों की मशीनों का भौतिक सत्यापन करती है व बजट आने पर सब्सिडी खाते मे डाल दी जाती है।

-सुरेंद्र मलिक

प्रदेश में खनन क्षेत्र में नई भावनाओं के साथ-साथ पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रदेश में माइनिंग माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। ओवरलोडिंग वाहनों के 450 करोड़ रुपए के चालान किये गए हैं।

पुलिस विभाग में महिला एसआई के 65 पदों पर भर्ती पूरी हो गई है। इनमें जनरल से 24, एससी से 12, बीसीए से 9, बीसीबी से 5, ईडब्ल्यूएस से 6, ईएसएम जनरल से 5 व एससी से एक, बीसीए एक, बीसीबी से दो पद तय किए गए।

हर हित स्टोर, दाम किफ़ायती

संगीता शर्मा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 अक्तूबर को गुरुग्राम से प्रदेश में 71 स्थानों पर एक साथ 'हर हित स्टोर' का लोकार्पण किया। कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के पांच हजार स्टोर खोलने की योजना है। इन स्टोर पर घरेलू उपयोगी 60 कंपनियों के 550 उत्पाद उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोज़गार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और स्वः रोज़गार के आयाम खड़े करके हम इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिला के फरूखनगर कस्बा में एक हर हित स्टोर का मौके पर जाकर उद्घाटन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री उस स्टोर के पहले ग्राहक बने। उन्होंने उस स्टोर से सामान खरीदा तथा उसका बिल भी अदा किया।

विपणन और ब्रांडिंग

- बाज़ार मानकों की तुलना में हरियाणा एग्रो फ्रैंचाइजी पार्टनर को बेहतर मार्जिन प्रदान करता है।
- फ्रैंचाइजी पार्टनर को दिया जाने वाला उत्पाद मिश्रण नवीनतम बाज़ार रूझानों पर आधारित होता है।
- हरियाणा एग्रो बाज़ार की गतिशीलता, प्रवृत्तियों, मौसमी और अन्य विभिन्न मूर्त और अमूर्त कारकों के आधार पर मुख्य उत्पादों को नया करता है।
- हरियाणा एग्रो ब्रांड व रिटेल आउटलेट के विज्ञापन, विपणन और प्रचार में फ्रैंचाजी पार्टनर की सहायता करता है। प्रचार कार्यक्रम रिटेल आउटलेट की बिक्री बढ़ाने और प्रस्तावित रिटेल व्यापार की प्रतिष्ठा और ब्रांड इक्विटी को विकसित करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे।

रिटेल आउटलेट का संचालन

- फ्रैंचाइजी पार्टनर को हरियाणा एग्रो के मानकों के अनुसार रिटेल आउटलेट और परिसर को संचालित करना होगा, जिनमें से कुछ इस खंड में दिए गए हैं। इस संबंध में फ्रैंचाइजी पार्टनर अपनी सहमति व्यक्त करता है कि -
- यह हरियाणा एग्रो के द्वारा बनाए गए समय अनुसार रिटेल आउटलेट को खोलेगा, संचालित करेगा व बंद करेगा और रिटेल आउटलेट को हरियाणा एग्रो के व्यापार के लिए ही उपयोग करेगा।
- फ्रैंचाइजी पार्टनर अपने आचारण के सामाजिक व कानूनी परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेवाद होगा।
- हरियाणा एग्रो किसी भी अप्रिय घटना के परिणाम के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार की क्षति/हानि शामिल है।
- फ्रैंचाइजी पार्टनर अत्याधिक सावधानी रखते हुए वैधानिक मानकों का पूर्ण अनुपालन और सामाजिक आचारण सुनिश्चित करेगा।
- हरियाणा एग्रो व उसके द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं से ही रिटेल आउटलेट के लिए उपकरण, फर्नीचर, पहचान सूचक साम्रगी आदि वस्तुओं को खरीदेगा और आवश्यकता अनुसार उन्हीं अनुमोदित आपूतिकर्ताओं से उपकरण आदि बदलवाएगा।
- केवल वही स्टॉक बेचेगा जो हरियाणा एग्रो द्वारा प्रदान किया जाता है।
- फ्रैंचाइजी समझौते पर अस्ताक्षर करने के एक महीने के अंतर्गत हरियाणा एग्रो को पहला उत्पाद / माल ऑर्डर अनिवार्य रूप से देगा।
- एक बार माल को उचित व परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से रिटेल आउटलेट पर पहुंचाने के बाद माल की क्षति के लिए हरियाणा एग्रो को किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं ठहराएगा।
- फ्रैंचाइजी पार्टनर अपने माल का आर्डर हरियाणा एग्रो द्वारा निर्धारित समय सारणी व अनुमोदित प्रणाली के अनुसार ही करेगा। यदि फ्रैंचाइजी पार्टनर निर्धारित प्रणाली का पालन नहीं करता है, तो हरियाणा एग्रो फ्रैंचाइजी पार्टनर को माल की आपूर्ति न करने व उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है।

स्वयं रोज़गार मिला हर हित स्टोर से

पानीपत राजीव कॉलोनी की कुटानी रोड में हर हित स्टोर खोला गया, जिसमें ज़रूरत का घरेलू सामान उपलब्ध है। इसकी संचालक प्रीति का कहना है कि यह स्टोर खुलने से गांव के लोगों को उच्चतम किस्म के उत्पाद घर के पास ही मिल रहे हैं और यहां ग्रामीण आकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें सामान रियायत दरों में मिलता है।

फ्रैंचाइजी पार्टनर के लिए पात्रता मानदंड

ग्रामीण व शहरी फ्रैंचाइज़ी आवेदकों के चयन के लिए सामान पात्रता मानदंड निम्न है।

पात्रता मानदंड	ग्रामीण फ्रैंचाइजी	लघु शहरी फ्रैंचाइजी	बड़ी शहरी फ्रैंचाइजी
आयु	21-35 वर्ष को प्राथमिकता	21-35 वर्ष को प्राथमिकता	21-35 वर्ष को प्राथमिकता
भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष	50 वर्ष	50 वर्ष
शैक्षिक योग्यता	12वीं पास	12वीं पास	12वीं पास
गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि	आवदेक न तो दोषी ठहराया गया हो न ही आपराधिक मामला लंबित हो	आवदेक न तो दोषी ठहराया गया हो न ही आपराधिक मामला लंबित हो	आवदेक न तो दोषी ठहराया गया हो न ही आपराधिक मामला लंबित हो
कोई वित्तीय दायित्व	सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में शून्य देयता हो	सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में शून्य देयता हो	सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में शून्य देयता हो
रिटेल आउलेट संचालन के लिए पूंजी	स्व-वित्तपोषित या मुद्रा ऋण	स्व-वित्तपोषित या मुद्रा ऋण	स्व-वित्तपोषित या मुद्रा ऋण
हरियाणा मूल निवास आवश्यकताएं	3,000 से अधिक जनसंख्या वाला गांव का मूल निवासी	10,000 से अधिक जनसंख्या वाला वार्ड का मूल निवासी	10,000 से अधिक जनसंख्या वाला वार्ड का मूल निवासी
रिटेल आउटलेट के लिए स्थान आवश्यकता	200 और उससे अधिक वर्ग फीट, भूतल और केंद्र बिंदु पर स्थित	200-800 वर्ग फीट, भूतल और केंद्र बिंदु पर स्थित	800 और उससे अधिक वर्ग फुट, भूतल और केंद्र-बिंदु पर स्थित

समाज को आलोकित करती साहित्य अकादमी

राज्य सरकार ने साहित्यकार सम्मान योजना के अन्तर्गत साहित्यकारों को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान राशि 7 लाख रुपए, महाकवि सूरदास सम्मान राशि 5 लाख रुपए, बाबू बालमुकुन्दगुप्त सम्मान, लखमीचन्द सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान तथा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान राशि 2.50 लाख रुपए की गई है। स्वामी विवेकानन्द युवा लेखक सम्मान तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान राशि एक लाख रुपए की गई है।

हरियाणा अधिवासी लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अधिकतम 25 हजार रुपए की गई है। वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में लगभग 100 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अनुदान राशि भी जारी की गई।

अकादमी द्वारा वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 के लम्बित साहित्यकार सम्मान (कुल 38) एवं वर्ष 2016, 2017, 2018 व 2019 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार (कुल 47) तथा पाण्डुलिपि पुरस्कारों (कुल 75) की राशि तथा पुस्तक प्रकाशन प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित 75 पुस्तकों में से 55 प्रकाशित पुस्तकों की 7 लाख रुपए की राशि लेखकों के खातों में जा चुकी है।

कोरोना महामारी के भय के खिलाफ शंखनाद, गुरु तेग बहादुर, हरियाणा की सभ्यता, मेघ मेखला, पंडित लखमीचंद एक अवलोकन आदि पुस्तकों के प्रकाशन सहित अकादमी द्वारा मार्च, 2021 के दौरान 8 लाख रुपए मूल्य की पुस्तकों की बि'ी भी की गई है।

नियमित मासिक पत्रिका हरिगंधा का अप्रैल अंक संस्मरण, मई-जून, 2021 संत साहित्य विशेषांक तथा जुलाई, 2021अंक कहानी विशेषांक आधारित रहा। सितम्बर मास में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालयों में अंग्रेजी-हिन्दी प्रशासनिक शब्दावली का नि» शुल्क वितरण किया गया।

16 सितम्बर को ऑनलाइन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन , 28 सितम्बर को मीडिया और साहित्य का सम्बन्ध विषय पर ऑनलाइन विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अक्तूबर, 2020 में वर्चुअल कवि सम्मेलन करवाया गया। 18 नवम्बर, 2020 को प्रदेश के तीन महान रचनाकारों महाकवि सूरदास, बाबू बालमुकुन्द गुप्त तथा पं. लखमीचंद की प्रतिमाओं को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा लोकार्पित किया गया।

23 जनवरी, 2021 को अकादमी अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री द्वारा श्रीमती धीरा खंडेलवाल की पुस्तक का लोकार्पण किया गया। अकादमी प्रवक्ता के मुताबिक अकादमी द्वारा वर्ष 2021 से हिन्दी तथा हरियाणवी भाषा की विभिन्न विधाओं में 15 नये युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार आरम्भ किए जा रहे हैं। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 31,000/- रुपए है।

लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए लोककवि दयाचन्द मायना सम्मान आरम्भ किया गया। विशेष हिन्दी सेवी सम्मान योजना 2021 में नया सम्मान लागू किया गया। जिसकी सम्मान राशि 1.00 लाख रुपये है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अकादमी का यू ट्यूब चैनल आरम्भ किया गया है। इसके अगले चरण में ई-बुक्स योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

-सुरेंद्र बांसल

हरियाणा उर्दू अकादमी की उपलब्धियां

हरियाणा स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में हरियाणा साहित्य संगम का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च 2017 तक मुख्यमन्त्री द्वारा उर्दू लेखकों को पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा को लागू कर दिया गया है।

29 जुलाई 2017 को अकादमी की ओर से अकादमी भवन में ग़ज़ल गायन का आयोजन किया गया। 30 अक्तूबर 2018 को में हरियाणा दिवस के अवसर पर मुशायरे का आयोजन किया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर हरियाणा उर्दू अकादमी की ओर से हरियाणा संवाद के प्रांगण में रू-ब-रू कार्यक्रम तथा मुशायरे का आयोजन किया गया। जिसमें श्री राजेश खुल्लर, आई.ए.एस, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषाएं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए।

25 जनवरी 2019 को जश्न-ए-अज़ादी के मौके पर पानीपत में ज़िला प्रशासन के सहयोग से एक मुशायरे का आयोजन किया गया। 22 फरवरी 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 23 फरवरी 2019 को अकादमी की ओर से हरियाणा कला परिषद् के सहयोग से बाल भवन चण्डीगढ़ में एक मुशायरे का आयोजन किया गया। डॉ. दिनेश दधीचि की पुस्तक ''शेष कुशल है'' का विमोचन किया गया।

अकादमी की ओर से हरियाणा के वर्ष 2019 के लिए उर्दू साहित्यकारों को वार्षिक सम्मान एवं पुरस्कार दिए गए। उसके लिए 22 अगस्त, 2019 को महामहिम राज्यपाल, हरियाणा की अध्यक्षता में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया दिनांक 16.02.2020 को 'मिर्ज़ा ग़ालिब' की पुण्य तिथि के मौके पर अकादमी सभागार में सेमिनार/मुशायरा आयोजित किया गया।

अकादमी की ओर से 2019 में डॉ. राणा गन्नौरी, श्री महेन्द्र प्रताप चाँद, डॉ. कुमार पानीपती, डॉ. हिम्मत सिंह सिंन्हा नाज़िम के फन और शख्सियत पर पुस्तकों के रूप में 'अदबी सिलसिला' प्रकाशन किया गया है। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका ''जमनातट'' का भी प्रकाशन नियमित जारी है।

कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2022 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2022 तक पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर किया जाएगा। पिहोवा के उपमंडल अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

हरियाणा वाणी एवं श्रवण निःशक्त जन कल्याण सोसायटी, पंचकूला को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में चुना गया है।

नानक तेरा - तेरा

नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया, जिसमें गृहस्थ और संन्यासी एक ही हैं। और वही आदमी अपने को सिक्ख कहने का हकदार है, जो गृहस्थ होते हुए संन्यासी हो, और संन्यासी होते हुए गृहस्थ हो।

सिक्ख होना बड़ा कठिन है क्योंकि सिक्ख का अर्थ है- संन्यासी, गृहस्थ एक साथ। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो। करना दुकान, लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना।

नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, वह मिली एक दुकान पर, जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल कर किसी को दे रहे थे। तराजू में भरते और डालते। कहते-एक, दो, तीन... दस, ग्यारह, बारह... फिर पहुंचे वे 'तेरा'। पंजाबी में तेरह का जो रूप है, वह 'तेरा'। उन्हें याद आ गई परमात्मा की। 'तेरा', दाईन, दाऊ-धुन बन गई। फिर वे तौलते गए, लेकिन संख्या तेरा से आगे न बढ़ी। भरते, तराजू में डालते और कहते 'तेरा'। भरते, तराजू में डालते और कहते तेरा। क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। तेरा से आगे कोई संख्या है? मंज़िल आ गई। 'तेरा' पर सब समाप्त हो गया।

लोगों को लगा कि नानक सामान्य दुनियादार नहीं। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और ही लोक में हैं। वे तो कहे जाते हैं 'तेरा'। डाले जाते हैं, तराजू से तौले जाते हैं, और तेरा से आगे ही नहीं बढ़ते। तेरा से आगे बढ़ने की जगह ही कहां है। दो ही तो पड़ाव हैं, या तो 'मैं' या 'तू'। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है।

नानक संसार के विरोध में नहीं हैं। नानक संसार के प्रेम में हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो। तुम इसी में उसको खोजो।

नानक जब युवा हुए, तब घर के लोगों ने कहा, शादी कर लो। उन्होंने 'नहीं' न कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में न आया कि मामला क्या है। भजन में, कीर्तन में, साधु-संगत में...।

भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। बीस रुपए दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था, सस्ती चीज़ खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना। यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहां आकर महंगे में बेच देना। यहां जो चीज़ सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेचना। वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज़ खरीदकर लाना, जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीदकर, मिल गई साधुओं की एक जमात। पांच दिन से भूखे थे वे साधु । नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो। उठो, कुछ करो। जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है। जब उसकी मर्ज़ी होगी वह देगा। तो हम आनंदित हैं। भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता।

तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं दूसरे गांव से? पिता ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग़ ख़राब हुआ है। नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने कुछ लाभ का काम करना। इससे ज्यादा लाभ क्या होगा? बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर लौटे।पिता ने कहा भी कि ऐसे तो व्यापार चौपट हो जाएगा। और नानक ने कहा, 'आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमा कर लौटा हूं।'

लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिलकुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था, लड़का साधु संगत में बिगड़ गया। होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी।

अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि संन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो, तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई क्योंकि यह आदमी किसी चीज़ के विरोध में न था। पिता ने कहा, 'शादी कर लो।'

नानक ने कहा, 'अच्छा'। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद न था।

तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर संन्यासी हो गया, उसे बिगाड़ सकते हो- धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर संन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। जिसने मान लिया कि सब 'तेरा ही तेरा' है , उसे किसी मेरे में फंसाया नहीं जा सकता।

– आचार्य रजनीश

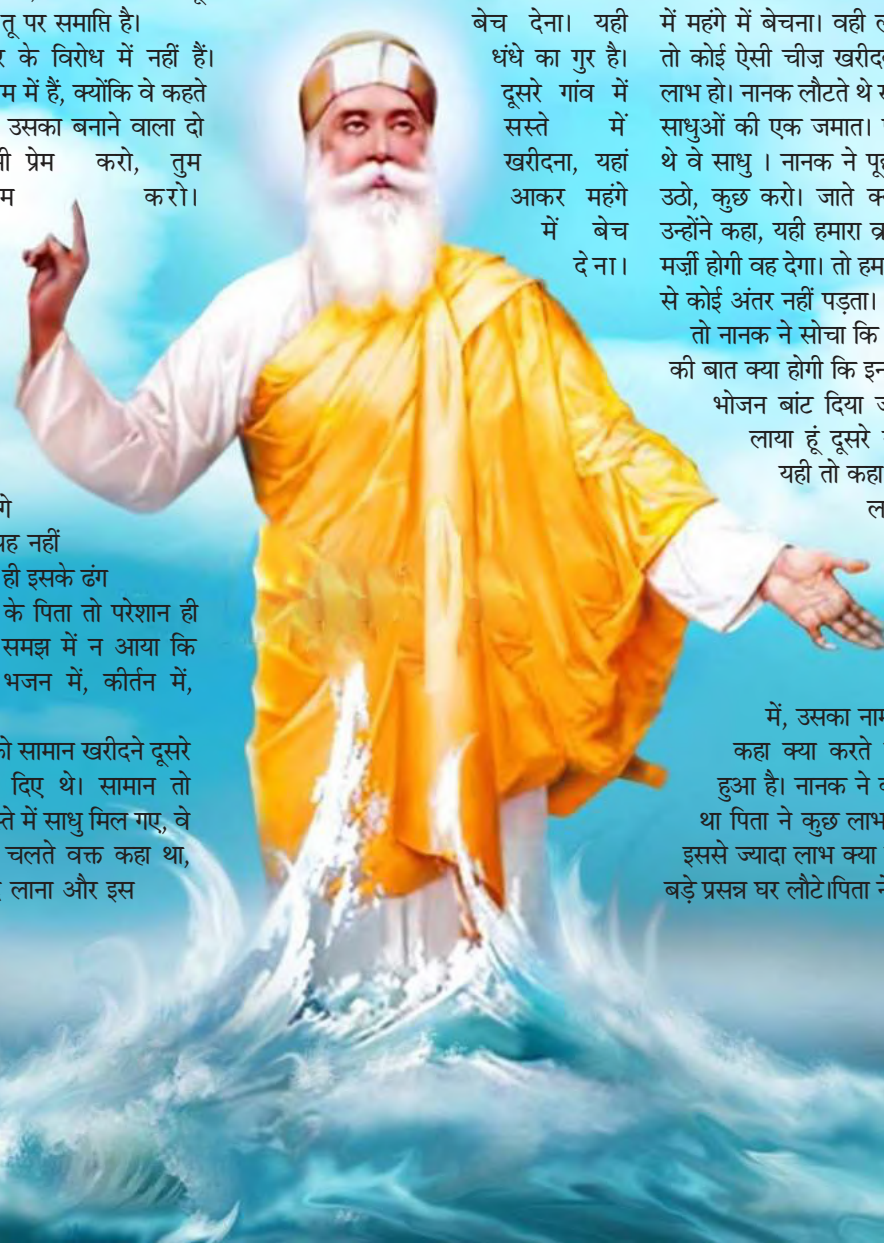

सुण छबीले बोल रसीले

बदल गए राजनीति के मायने

छबीले ने शहर जाने के लिए अपनी पुरानी बाइक उठाई। थोड़ी दूर गली में चला था तो रसीले के घर के बाहर रुक गई। कई बार किक लगाई लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। देखा तेल कम है। तेल को रिजर्व लगाने वाली नोब टूटी हुई थी, उसे घुमाने के लिए प्लास की जरुरत पड़ गई।

छबीले ने रुक्का दिया- अरै रसीले, प्लास लेर्‌या सै के?

रसीला बोल्या- प्लास तो कोनी छबीले, माचिस लेर्‌या सूं। एक ना आधी, दो दो।

छबीले ने कहा उसनै के मैं सिर में मारुंगा?

- आग ला दिए।

-भूंडा बोलै, शरमा ले। भाभी नै बताद्यूंगा।

-बता दे मैं के डरूं सूं।

-मनैं तेरे तैं कितणी बार कह ली, यो बाइक पुराणी हो ली, नई ले ले।

-बात पुरानी, नई की कोन्या, कई दिन पाछै काढ़ी सै। ज्यांए तै अळबाद कर री सै।

-इसनै आड़ीए छोड़ दे, ले चाबी, म्हारी आली बाइक ले ज्या। पर तूं शहर तैं के ल्यावैगा?

-दिवाली सै, बालकां खातर ले आऊं किमे बम-पटाके और खाण-पीण का सामान।

-छबीले, बम पटाक्यां तैं पर्यावरण खराब होवै सै, मिठाइयां की शिनाख्त कोन्या। क्यूं खर्चा करै सै।

-अरै रसीले, कुछ तो ल्याणा पड़ैगा।

-देख छबीले, मोमबती की जगहां माटी के दीए में सरसों का तेल जळाना चाहिए। तेल या घी के दीए जळाने तैं घर की सारी ओपरी-पराई ऊर्जा का नाश होज्या सै और घर में सुख समृद्धि का आगमन होवै सै। जड़ै सकारात्मक ऊर्जा हो उड़ै धन लक्ष्मी का आगमन हो सै। इस लिए तो दिवाली पै दीपक जलाणे की परंपरा सै। पुराणे बख्ता में जिब म्हारी मां और दादी सरसम के तेल की बाती जलाकै म्हारी टोक तार्‌या करती। उसका यूए वैज्ञानिक कारण था, तेल के दीपक से निकलने वाली उष्मा व धूएं से उस क्षेत्र के छोटे मोटे किटाणु मरज्यां सैं और हवा शुद्ध होज्या सै। उस तेल की बाती तै हलवे आले पलटे पर आंख्या का काजल बणाया करती, वो बहुत बढ़िया दवाई थी। ईब आली लुगाइयां नै इस बारे में कुछ ज्ञान कोन्या।

जड़े ताहीं रही बात खाणे-पीणे की। बाजार में तो मिठाई नकली भी पा सकै सै। आपणे घर नै देसी घी का हलवा बणा। खुद भी खा और मनै भी खुआ।

देख फेर क्यूकर दिवाली मन्या करै।

-रसीले

एक तो बात सै, तूं या तो बोलता नहीं, बोलै सै जिब बढ़िया बोलै सै। एक काम कर, तूं इबकै एमएलए का लेक्शन लड़ ले।

-बावला सै छबीले, राजनीति में ईब वो बात कोन्या रही। जिब तैं देस प्रदेश में ये सरकार आई सैं, राजनीति के मायने बदलगे।

- वो क्यूकर भाई?

- छबीले, विधायक हों या मंत्री किसे नै लाल बत्ती आली गाड़ी नहीं मिलती। इस सरकार नै इसा सिस्टम बांध दिया अक नेताओं के कहने पै ना तो कोई नौकरी लाग सकता और ना कोई बदली करा सकता। इनै कामां खातर लोग इनके आगै-पाछै लागे रहा करते। ईब कोई किसे कै पाछै लागता नहीं दिखता। सारी भीड़ छंटगी। बेरा भी ना पाटता पड़ौस में किब कोई मंतरी संतरी आया और चल्या गया।

-भाई रसीले इस सरकार नै काट्या यू क्लेश। दो नंबर के सारे काम धंधे बंद कर दिए।

-हां भाई, नौकरी योग्यता के आधार पै लागै सैं और बदली आनलाइन होज्या सैं। पहल्यां ये सारे काम पर्ची और खर्ची में होया करते। जिबै तो लोग राजनीति कानी भाज्या करते। ईब बालक या तो पढ़ाई करैं सैं या काम धंधा जमा ले सैं।

-रसीले कुल मिलाकै ठगा-बगी बंद होगी। तो फेर जाण दे राजनीति नै, ल्या बाइक की चाबी दे, शहर तै दाल चावल और हलुवे खातर सूजी ले आऊं।

-मनोज प्रभाकर

दीवाली

दीपों का त्योहार दीवाली।
लाये खुशी अपार दीवाली।।
इक दूजे को गले लगाओ,
प्यार से सरोबार दीवाली।
अंधेरे से प्रकाश की ओर,
लेकर जाये हमें दीवाली।
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई,
सब में बांटे प्यार दीवाली।
आतिशबाजी धूमधड़ाके से
दूर हो अबकी बार दीवाली।
आओ प्रदूषण मुक्त मनाए,
मिल करके इस बार दीवाली।

-भूपसिंह भारती

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com